Hkkjrh; turk ikVhZ
jk"Vªh; dk;Zdkfj.kh
29&30 ebZ] 2006] ubZ fnYyh

v/;{kh; Hkk"k.k

भारतीय जनता पार्टी के रजत जयंती समारोह के दौरान मुम्बई में सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज हम दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिल रहे हैं। मेरी अध्यक्षता में हो रही यह पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बठैक है। मुंबई अधिवेशन की चर्चा आते ही लगता है कि प्रमोदजी सामने खड़े हैं। पर यह सच नहीं है। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बिना प्रमोदजी के हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। समाज जीवन के कार्य में अनेक असहनीय आघात सहने पड़ते हैं। प्रमोदजी के अचानक चले जाने के आघात को भी हमें सहन करते हुए संगठन कार्य को आगे बढ़ाने में जुटना होगा।

भारतीय जनता पार्टी असीम क्षमताओं वाली पार्टी है। आज हमारे कार्यकर्ता अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तुलना में ईमानदार, संघर्षशील और क्षमतावान हैं। देश में जितने भी दल हैं उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यदि कोई दल कार्य कर रहा है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी। हम सबल नेतृत्व के धनी हैं। आज मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और नागालैंड में हमारी और हमारे गठबन्धन की सरकारें हैं। राजनीतिक तौर पर हम एक प्रभावी राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बावजूद इसके हमें अनेक राज्यों में अपने कार्य का प्रभावी विस्तार करना है। भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अनेक राज्यों सहित केन्द्र में कांग्रेस की स्थापित सत्ता को चुनौती देते हुए न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया बल्कि उससे बेहतर सरकार चलाकर भारत की राजनीति के मूल ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने का कार्य किया। आगे भी प्रकृति हमारे मार्ग प्रशस्त करेगी। देशवासी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भारत का भविष्य भाजपा के हाथ में ही सुरक्षित है। कश्मीर से लेकर केरल तक की राष्ट्रीय समस्याओं के लिए भाजपा ही एकमात्र दल है जो वोटों की राजनीति से परे जनहित के लिए मैदान में संघर्ष करती है।

gky esa lEiUu fo/kku lHkk pquko

भारतीय जनसंघ काल से लेकर आज तक की अपनी लंबी जीवन यात्रा में भाजपा ने तमाम उतार–चढ़ावों के बावजूद अपनी राजनैतिक क्षमता को भारत की राजनीति में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

हाल में सम्पन्न विधान सभा चुनावों में भाजपा ने सभी राज्यों में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा। हमारे इस प्रयास का निहितार्थ केवल प्राप्त सीटों की संख्या से नहीं निकाला जा सकता। संगठन के विस्तार और विचारधारा के प्रसार की दृष्टि से हमने एक सार्थक प्रयास किया है। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में प्राप्त परिणाम को देखते

हुए हमें इन राज्यों में अपने कार्य की आगामी दिशा तय करनी होगी साथ ही वहां पर एक ऐसी व्यूह रचना बनानी होगी जिससे इन राज्यों में हमारे प्रभाव का विस्तार हो। हमें विश्वास है कि भविष्य में इसके बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। असम में हमारे प्रयास के संतोषजनक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े।

असम में हमारा मत प्रतिशत और सीटें दोनों बढ़ी हैं। जबकि पिछला असम विधान सभा का चुनाव हम गठबंधन के साथ लड़े थे और इस बार हम अकेले लड़े थे। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी सीटों की वृद्धि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। असम में हमने भौगोलिक विस्तार भी प्राप्त किया है। पहली बार हमें ब्रहमपुत्र घाटी में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मैं यह कह सकता हूं कि इन चुनावों में भाजपा को असम में एक प्रबल राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है।

Hkkjr lqj{kk ;k=k

भारतीय जनता पार्टी ने भारत सुरक्षा के माध्यम से गत 6 अप्रैल से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जनजनागरण अभियान चलाया। गुजरात के द्वारिका से माननीय आडवाणी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी से मैं स्वयं रथ यात्रा लेकर देशवासियों के बीच गए। यूपीए सरकार की गलत नीतियों से बढ़ते आतंकवाद और तुष्टिकरण की नीतियों के साथ–साथ बढ़ती महंगाई के मुद्दे को जन–जन के बीच उठाया। यात्रा के दौरान हमारा जनता से सीधा संवाद हुआ। इस यात्रा में कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जहां पर सूर्यास्त के बाद लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं, वहां पर नक्सली आतंक की परवाह किए बिना विशाल जनसमूहों ने जिस प्रकार यात्रा का स्वागत किया उससे हमें यह विश्वास हुआ कि जिन मुद्दों से भाजपा चिंतित है उससे देश के सुदूरवर्ती अंचलों की आम जनता भी उतना ही चिंतित है।

यूपीए के सरकार के नरम रवैये और गलत नीतियों से आतंकवादियों और नक्सलवादियों का हौसला बुलंद हुआ है। देशभर में हिसंक हमले हो रहे है।। ऐसे में भारत सुरक्षा यात्रा के माध्यम से यूपीए सरकार को जनता के आक्रोश का अहसास कराने में हम सफल रहे। यात्रा के दौरान देशवासियों को हमने अपनी विचारधारा तथा सैद्धांतिक विषयों से जोड़ने का प्रयास किया। मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय आडवाणी जी का रथ चिलचिलाती धूप में भी कहीं नहीं रूका। इस उम्र में उनकी जीवटता उनका अदम्य साहस हम सबके लिए प्रेरणादायी है। हम सभी लोगों को ज्ञात है कि यात्रा 10 मई को दिल्ली में समाप्त होनी थी। परन्तु प्रमोदजी के दुखद निधन के कारण हमें 3 मई को ही यात्रा समाप्त करनी पड़ी।

समान नागरिक संहिता कोई राजनैतिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्र के एकात्म स्वरूप की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय के पक्ष में एक नहीं दो–दो बार निर्देश दिये हैं। अनेक संविधान विशेषज्ञों के साथ–साथ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रह चुके व्यक्तियों ने भी इस विचार का समर्थन किया है। यह विचार संविधान की मूल भावना से प्रेरित है। आज देश की वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता और भी प्रसांगिक हो गयी है। अतः इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।

ns'k ds lkeus pqukSfr;ka

केन्द्र में एन.डी.ए. सरकार को गये हुए और यूपीए गठबन्धन की सरकार को आये हुए दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन दो वर्षों में अक्षम राजनैतिक नेतृत्व के चलते देश में अनेक जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। देश के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक तीनों क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर जैसा आघात यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

आज राष्ट्र के समक्ष बहुत बड़े खतरे खड़े हो गये है। कांग्रेस के ही राज में तिब्बत के मुद्दे पर ऐतिहासिक भूल हुई थी और आज नेपाल के मुद्दे पर कांग्रेस उसी भूल को फिर दोहरा रही है। भारत नेपाल के बीच 1751 कि.मी की खुली एवं निर्बाध सीमा है, भारत में 22 लाख से अधिक नेपाली रह रहे हैं। जिन्हें भारतीयों के समान सभी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय सेना में गोरखा समूह का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व है। यदि इस स्थिति में नेपाल में भारत के प्रति प्रतिकूल भाव रखने वाली सत्ता आती है। तो इसका सीधा असर हमारे आन्तरिक मामलों पर पड़ेगा। आज नेपाल के माओवादी, बांग्लादेश के आतंकवादी और आईएसआई के बीच सांठगांठ की खबरें आ रहीं हैं। यह तय नहीं हो पाया कि भारत के वामपंथी नेपाल किसका एजेंडा लेकर गए थे, मनमोहन सरकार का या माओवादियों का। नेपाल की इस जटिल स्थिति के लिए मैं यूपीए सरकार को दोषी मानता हूं। क्योंकि **bl ljdkj us le; jgrs gq, usiky ds eqís ij dkbZ lkFkZd i;kl ugha fd;kA**

fons'k uhfr

इस सरकार का विदेश मंत्री वोल्कर का शिकार हो गया। तब से इसका कोई विदेशमंत्री ही नहीं है। सरकार की विदेशनीति प्रॉक्सी पर चल रही है अथवा सीपीएम के दिशा निर्देश से चल रही है। नेपाल में हस्तक्षेप करने के बाद अब वामपंथी श्रीलंका में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। सम्भवतः प्रधानमंत्री सरकार के बाहर के किसी दल के द्वारा विदेश मंत्रालय चलाने का अजीबों–गरीब प्रयोग कर रहे हैं। इससे पूर्व भी वामपंथी पार्टियों ने ईरान और ईराक के मसले पर और अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर अल्पसंख्यकों में मजहबी जुनून उभरने का कार्य किया है। मैं यहां प्रधानमंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

यह सरकार देश को कहां ले जाना चाहती है। वामपंथी और कांग्रेसी मिलकर केरल की विधानसभा में कोयम्बटूर कांड के मुख्य आरोपी को पेरोल पर रिहा करने का प्रस्ताव पारित करवाते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार देशद्रोह के आरोपी को राज्य की विधायिका का समर्थन दिए जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अमेरिका के साथ हुए आणविक समझौते को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आशंकाए व्यक्त की थीं वो सत्य होती दिख रही हैं। आण्विक ऊर्जा के विस्तार के नाम पर भारत की आण्विक प्रतिरक्षा के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह उठ रहा है। समझौते के विषय में प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिया गया विवरण अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष उपलब्ध

विवरण के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर यूपीए सरकार ने संसद को गुमराह किया।

यूपीए सरकार ने अग्नि–ष्ष् का परीक्षण रोककर पूरे राष्ट्र को सशंकित कर दिया। रक्षा मंत्री द्वारा परीक्षण न करने को स्व–निर्धारित कहना भारत सरकार के स्वयं के विचार से निर्धारित है अथवा शक्तिशाली राष्ट्रों की रणनीतिक आवश्यकताओं से निर्धारित है। हर जागरुक नागरिक यह जानना चाहता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इसके द्वारा हमारे स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को एक धक्का पहुंचा है। जबकि अप्रैल 1999 में माननीय अटल जी की सरकार ने भारत पर लगे हुए कड़े आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों के बावजूद अग्नि–ष् का परीक्षण किया था। अतः हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में राष्ट्र की प्रतिरक्षात्मक शक्ति को जो मजबूती प्रदान की थी वह यूपीए सरकार के इस कदम से कमजोर हुई है।

iMklh n'k

आज देश के सभी पड़ोसी देश भारत विरोधी शक्तियों के केन्द्र बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से तो ऐसी गतिविधियां लम्बे समय से चल रहीं हैं। अब बांग्लादेश से भी विघटनकारी गतिविधियों का संचालन हो रहा है। नेपाल के हालात पर चिंता हम पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। श्रीलंका में लिट्टे पुनः सक्रिय होता दिख रहा है तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान फिर से सिर उठा रहा है। इस परिस्थिति को यूपीए सरकार की विदेशनीति की असफलता ही कहा जाएगा।

पाकिस्तान से आण्विक और समरिक तकनीकों की कालाबाजारी भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। डोडा से लेकर दिल्ली तक और बनारस से लेकर बंग्लोर तक आतंकवादी जब, जहां और जैसे चाहते हैं नरसंहार कर निकल जाते हैं। इतना ही नहीं भारत सरकार हुर्रियत नेताओं को केवल पाक अधिकृत कश्मीर तक जाने की अनुमति देती है और पाकिस्तान सरकार उन्हें इस्लामाबाद तक ले जाती है। भारत सरकार इस पर कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है।

माननीय अटल जी की सरकार ने पाकिस्तान पर जबर्दस्त दबाव बनाया था और जनरल मुर्शरफ से यह वायदा करवाया था कि वो पाकिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। परन्तु इस सरकार ने मानो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर–ए–तयैबा अपना नाम बदलकर 'जमातुद्दावा' के रूप में पाकिस्तान से आतंक फैलाना जारी रखे हुए है। यूपीए सरकार चाहे तो इस मुद्दे को सप्रमाण सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के अन्तर्गत रखकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रयास कर सकती है।

सामरिक रणनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सियाचीन ग्लेशियर से सेना की वापसी का जो संकेत सरकार ने दिया है। उससे देश की जनता ही नहीं बल्कि भारतीय सेना भी स्तब्ध है। देश के इतिहास में पहली बार केवल दो महीने के अंदर दो बार देश की सेनाप्रमुख को सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले सेना में मुस्लिमों की गिनती के विषय पर और फिर सियाचिन से सेना की वापसी के विषय

पर। पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सियाचिन जैसे महत्वपूर्ण स्थान से सेना की वापसी को भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

vkUrfjd lj{kk

इसी महीने जम्मू काश्मीर के डोडा और ऊधमपुर में 32 हिन्दुओं का नरसंहार हुआ। उसके बाद भी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर सिद्ध हुई कि भाजपा के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद भी सरकार अपनी ही रैली पर आतंकवादी हमला होने से रोक नहीं पाई। यह आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की अक्षमता का ज्वलंत उदाहरण है।

आज काश्मीर में एक विस्फोटक स्थिति दिखाई पड़ती है। काश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू से भी हिन्दू और सिखों को पूरी तरीके से भगा देने का एक अभियान चल रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन इसकी स्पष्ट घोषणा भी करते हैं। सुरक्षा मी मांग कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया जिसमें दो कार्यकर्ता शहीद हो गये। काश्मीर भारत की संप्रभुता के लिए तो एक चुनौती था ही अल्पसंख्यक हिन्दुओं के योजनाबद्ध सफाए के चलते भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए भी एक चुनौती बन गया है। राजनैतिक रैलियों पर आक्रमण के द्वारा भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पर भी काश्मीर में प्रश्नचिन्ह लगना शुरु हो गया है। अतः **tEe dk'ehj Hkkjr dh liHkrk] /kefujis{krk vkj ykdr= ;k ;s dg fd Hkkjr d lex jk"Vh; Lo:i d fy, pukrh cu pdk gA**

इस काश्मीरी हिन्दुओं की शरणार्थी शिविरों में दुर्दशा यथावत है। इन सारी परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मैं देश के सभी राजनैतिक दलों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो हालात की नजाकत को पहचानें और धारा 370 के संदर्भ में अपने नजरिए पर दोबारा विचार करें। मेरा यह मानना है कि आज धारा 370 के विषय पर विचार करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

केवल काश्मीर में ही नहीं काशी में संकट मोचन मंदिर पर हुआ हमला हो अथवा पैगबंर मोहम्मद के कार्टून को लेकर चले विवाद के दौरान लखनऊ में और बाद में अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे हों अथवा उत्तर प्रदेश के ही मऊ में हुआ नरसंहार। यह सब हमारे विरोधी दलों द्वारा पैदा किए जा रहे साम्प्रदायिक उन्माद के ज्वलंत उदाहरण हैं।

uDlyh vkrdokn

देशभर में नक्सली आतंकवाद बहुत तेजी से आपने पांव फैला रहा है। यह देश की आन्तरिक सुराक्षा के लिए उठता हुआ एक नया खतरा है। केन्द्र की सत्ता प्राप्त होने के बाद यूपीए सरकार ने नक्सलियों के प्रति जो नरम नीति अपनाई उसक चलते नक्सलवाद को विस्तार भी मिला और शक्ति भी बढ़ी। केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2004–05 के बीच नक्सली हिंसा में मोरे गए लोगों के संख्या में 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष 1000 नए कैडर जुड़ने से नक्सलियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज देश का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र और लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या नक्सलवाद और आतंकवाद की चपेट में आ चुका है। यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों से महंगाई

और बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे उत्पन्न असंतोष का लाभ उठाकर नक्सली विशेष रूप से नौजवानों को गुमराह करके उनके हाथों में हथियार थमा रहे हैं। नक्सलवादी देश की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने में लगे हैं और सरकार इस संकट के निदान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

vfu;f=r eY;of)

पिछले दो वर्षों में सामान्य उपभाग की वस्तुओं के दाम जितनी तेजी से बढ़े हैं कि आम आदमी स्तब्ध रह गया है। आटा, दाल, चावल, फल–सब्जी, नमक, शक्कर, से लेकर पेट्रोल–डीजल और रसोई गैस और किरोसिन तेल तक हर चीज के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। एक बार पुनः पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे है। वहीं दूसरी ओर इन वस्तुओं की कालाबाजारी से आम आदमी और अधिक त्रस्त हो रहा है। एनडीए सरकार के शासनकाल में महंगाई और कालाबारी पर पूरा नियंत्रण पा लिया गया था। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब–जब कांग्रेस सत्ता में आती है महंगाई और कालाबाजारी बढ़ जाती है। जनता इसका जबाव चाहती है। आवास ऋण पर ब्याज की दरों में भारी कटौती करके हमारे सरकार ने जहां आम आदमी के लिए घर के सपने को साकार करना शुरु किया था तो वहीं यूपीए सरकार के आने के बाद लगातार बढ़ती ब्याज दरों ने एक बार फिर आम आदमी के अपने घर के सपने को चकनाचूर कर दिया है।

आम आदमी पर बढ़ रहे इस आर्थिक बोझ के बावजूद सरकार के समर्थक शेयर बाजार के बढ़ते रहने को अर्थव्यवस्था की सफलता का प्रमाण बता रहे थे। सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दिन ही वह भ्रम भी टूट गया। 22 मई को शेयर बाजार में आई भीषण मंदी ने देश के केवल औद्योगिक जगत हो नहीं बल्कि उन दो करोड़ छोटे निवेशकों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस सरकार के कार्यकाल में मंदी के कारण कारोबार रुकने का यह तीसरा अवसर था। वित्तमंत्री इसे 'मेनुफैक्चरड क्राइसिस' कह रहे हैं। भाजपा देश के तमाम छोटे निवेशकों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री से यह जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस समस्या की संरचना की है। सेवी ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की। पांच दिन के अन्दर 2000 अंक नीचे आते हुए सूचकांक के समय में क्या वित्तमंत्री की भूमिका न्याय संगत थी?

बढ़ती मंहगाई ने जहां गरीबों को छला है, वहीं रोजगार गारंटी योजना के नाम पर बगैर किसी समुचित आर्थिक प्रावधान के योजना की घोषणा करके देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ भी मजाक किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि यूपीए सरकार का उद्देश्य बेरोजगारों का कल्याण करना नहीं बल्कि केवल राजनैतिक वाहवाही लूटना रह गया है।

fdlkuk dh leL;k,

यूपीए सरकार की लचर आर्थिक नीतियों के चलते किसानों पर बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव उन्हें लगातार निराशा में धकेल रहा है। देश के अनेक राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं। एनडीए सरकार की तमाम कृषि सम्बन्धी नीतियों को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। हमारी सरकार के समय में जहां हमारे खाद्यान्न भण्डार भरे हुए थे और हम खाद्यान्न को निर्यात कर रहे थे वहीं आज स्थिति में इतना बदलाव आया है कि हमें उल्टा खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा है और वह भी विदेशी गेहूं को स्वदेशी गेहूं से

अधिक मूल्य पर खरीद कर किया जा रहा है। इस कार्य में भी सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई फर्म ए.डब्ल्यू.बी. लिमिटिड जैसी फर्म के माध्यम से करवाया है जो वोल्कर जांच आयोग में दोषी पाई जा चुकी है। यानि किसानों की दुर्दशा देश के खाद्यान्न समस्या के बीच में भ्रष्टाचार के संकेत दिखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए कोई गंभीर प्रयास सरकार की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा। किसानों की इस दुर्दशा को पूरी संजीदगी के साथ लेते हुए भाजपा ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में धरना दिया वहीं कृषि मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है।

rsyaxkuk dk lkFk /kks[kk

दो वर्ष पहले कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि यदि वे विजयी होते हैं तो वे आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्य को बांटकर एक संपूर्ण तेलंगाना राज्य बना देंगे। दोनो दल विजयी हुए, परन्तु तेलंगाना राज्य की बात कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी है। मैं पिछले दिनों आंध्रप्रदेश के दौरे पर गया था। अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने 'तेलंगाना' राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैंने वहां पर सार्वजनिक रूप तेलंगाना की जनता की भावनाओं के अनुरूप यह घोषणा की कि तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए। हम प्रारम्भ से ही छोटे राज्यों के समर्थक रहे हैं। एनडीए की सरकार में मा. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्रित्वकाल में ही हमने अपने चुनाव पूर्व वायदे के अनुसार तीन नए राज्यों का निर्माण किया। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। हम चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य बने। मा. आडवाणीजी ने भारत सुरक्षा यात्रा के समय तेलंगाना के पक्ष में भाजपा का मत स्पष्ट किया है। यदि लोकसभा में तेलंगाना बनाने का प्रस्ताव आता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। आंध्रप्रदेश के कार्यकर्ताओं में खासकर तेलंगाना इलाके में अपनी पार्टी की ओर हुई घोषणा का सभी ने चारों ओर सराहना की।

laoS/kkfud 0;oLFkkvksa dk {kj.k

यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत के अनेक संवैधानिक संस्थानों की गरिमा को गंभीर क्षति पहुंचाई है। सरकार के ऐसे क्रियाकलापों की एक लंबी श्रृंखला है।

इस सरकार ने आने के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया।

पहली बार राज्यपालों को कार्यकाल के बीच में हटाया और फिर गोवा, झारखंड और बिहार में राज्यपाल जैसे गरिमामय संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग का एक काला अध्याय लिखा।

आईएमडीटी एक्ट और मुस्लिम आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के बाद सरकार की प्रतिक्रिया न्यायपालिका के प्रति अवमानना की स्पष्ट प्रतीक रही।

कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जहां चुनाव आयोग की सार्वजनिक आलोचना करते दिखाई पड़े तो वहीं सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री तो चुनाव आयोग को केवल पक्षपाती भी नहीं बल्कि जातिवादी कहते हुए भी दिखे। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा पर ऐसा आघात पिछली किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ।

लाभ के पद के मुद्दे पर लाये गये विधेयक में कहीं कोई नियम न बना कर सीधे पदों की सूची का उल्लेख किया गया है। इस मुद्दे पर देश की पूरी संसद को अपनी मर्जी से पहले स्थगित करना और फिर अपनी सुविधा से उसका सत्र पुनः बुलाना, यह दर्शाता है कि सरकार संसद को भी अपनी सुविधा का एक उपकरण बनाना चाहती है।

इन सारे उदाहरणों के आधार पर यदि यह कहा जाय कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गहरा आघात पहुंचाया है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

lkekftd fo?kVu

/kekZUrj.k

lkekftd {k= में यूपीए सरकार ने ऐसा लगता है सामाजिक विघटन की एक सुनियोजित प्रक्रिया शुरू कर दी है। घुसपैठ, धर्मान्तरण और नरसंहारों के द्वारा भारत के पूरे जनसांख्यिकी स्वरूप को बदलने का एक सुनियोजित षडयंत्र आज देश में चल रहा है। और यूपीए सरकार की नीतियों से इसे बल मिल रहा है। देश में गरीबी और अशिक्षा के कारण छल–बल और प्रलोभन से हो रहा धर्मान्तरण सर्वथा अनुचित है। इसकी इजाजत संविधान भी नहीं देता। ऐसे धर्मान्तरण के प्रयासों को सर्वोच्च न्यायालय भी अनुचित मानता है। इस गंभीर सामाजिक मसले को राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

rf"Vdj.k

जमात–ए–इस्लामी हिन्द जैसे संगठन यदि मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग करते थे तो नियंत्रित करने की बजाय कांग्रेस ने आन्ध्र प्रदेश की सरकारी नौकरियों और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुस्लिमों को आरक्षण देने असंवैधानिक प्रयास किया। इतना ही नहीं सेना में मुसलमानों की गिनती करवा कर साम्प्रदायिक मतभेद को और गहरा करने का कार्य किया।

vkj{k.k

यूपीए सरकार ने आरक्षण के मसले से अपने राजनैतिक हित साधने का जिस तरह से प्रयास किया है उसने सामाजिक समरसता के स्थान सामाजिक तनाव उत्पन्न करने का कार्य किया है। भाजपा ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के विधेयक का संसद में समर्थन किया है। परन्तु इस प्रक्रिया में वैमनस्य और विभेद उत्पन्न होने से रोका जाना चाहिए। देश की सामाजिक संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यथासंभव आम सहमति के प्रयास किये जाने चाहिए। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण को लागू करते समय योग्यता और प्रतिभा का दमन न हो। और हमारे श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता यथावत बनी रहे। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आरक्षण का वास्तविक लाभ पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक पिछड़े और वंचित समूहों तक पहुंच सकें। सरकार को अगड़ी जातियों के निर्धन छात्रों को भी आरक्षण के लाभ की परिधि में लाना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरक्षण की परिधि से बाहर रखने के स्पष्टतः खिलाफ है। साम्प्रदायिक आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए।

Hkkt ik&vrhr] orZeku vkSj Hkfo";

एक राजनैतिक दल के रूप में भाजपा का अतीत बहुत गौरवपूर्ण रहा है। देश की राजनीति के हर कालखंड में और हर परिस्थितियों में भाजपा ने अपने को एक सक्षम राजनैतिक दल के रूप में स्थापित किया है।

भारतीय जनसंघ के रूप में अपने जीवनकाल में 1951 से लेकर 1977 हमने अपने आप को एक सुदृढ़ विचारधारा वाले राजनैतिक दल के रूप में स्थापित किया। 1980 में भाजपा के नए रूप में आने के बाद 1980 से 1998 तक उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए विचारधारा के साथ–साथ एक गतिशील संगठन वाले विशिष्ट राजनैतिक दल के रूप में हम देश की सत्ता तक पहुंचे। 1998 से 2004 तक केन्द्र में गठबन्धन सरकार का कुशल संचालन करके हमने विचारधारा और संगठन के साथ–साथ गठबन्धन की राजनीति में भी अपनी कुशलता की अमिट छाप भारत की राजनीति पर छोड़ दी। अर्थात हमने विचारधारा, संगठन और गठबन्धन तीनों क्षेत्रों में भारत की राजनीति में अपने को एक अलग और अग्रणी दल के रूप में स्थापित किया है।

हमारी पार्टी की एक विशिष्ट पहचान रही है। जनता में भाजपा की एक विशिष्ट छवि और भाजपा से विशेष अपेक्षाऐं रहीं है। परन्तु आज हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी उस विशिष्ट छवि को लेकर कई प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हम सब को मिल कर देना होगा। मैं आप सबसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हम विचार करें कि यह प्रश्न खड़े करने के अवसर ही क्यों हुए। इसके लिए हमें सोचना होगा और आत्मनिरीक्षण करना होगा।

अनुशासन हमारी विशिष्टता का एक प्रमुख आधार है। 'अनुशासन' में रहकर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। इस बात को जानते हुए भी पिछले कुछ वर्षों में इस मामले में मर्यादाएं टूटी हैं। इसे हम और आपमें से कोई भी उचित नहीं मानेगा। अनुशासनहीनता जिस स्तर पर भी हो, हमें उसके प्रति कठोर होना होगा। अन्यथा हमारी भी गति अन्य दलों की भांति होते देर नहीं लगेगी।

मेरा मानना है कि हमारी पार्टी की सोच सैदव कार्यकर्ता आधारित रही। पार्टी के सामूहिक कार्यक्रमों के साथ–साथ हम सब कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत क्रियाकलाप जनहित के कार्यों से जुड़े रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में कार्य करते समय हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारे कार्यों का और प्रयासों का लक्ष्य विपक्ष में रहते हुए जनसमस्याओं के लिए संघर्ष और सत्ता में रहते हुए जनसमस्याओं का निदान है न कि स्वयं का प्रचार। हमारे प्रयास राजनीति में व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर हमारी प्रतिबद्धता और जनहित के अनुरूप होने चाहिए।

केन्द्र में हमें सत्ता से बाहर हुए 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्ष 2004 के लोकसभा में वांछित सफलता न मिलने के कई कारणों की समीक्षा हो चुकी है। मैं एक अकेले तथ्य को इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी मानता हूं और वह है हमारे 50 प्रतिशत सांसदों का दोबारा निर्वाचित होकर न आ पाना। हमें यह विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं जनसमस्याओं के उपचार के हमारे प्रयास जनता के मन में वांछित स्थान नहीं बना सके। यह उदाहरण एक चुनौती है और एक सबक है। हमारी पार्टी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए, संगठन के समस्त पदाधिकारियों के लिए और विशेषकर उन राज्यों के लिए जहां हम सत्ता में हैं।

जनता, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के बीच सम्पर्क और संवाद हमारे लिए प्राणवायु हैं। इसे सत्त और ऊर्जावान बनाये रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।

हमारी सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन पर बहुत बड़ा दायित्व है। भाजपा एवं हमारे गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में आम जनता को इस आशय का एहसास होना चाहिए कि यह हमारी सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों के साथ–साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका व्यवहार समाजोन्मुखी और कार्यकर्ता के अनुरूप रहना चाहिए।

IxBukRed p|uko

भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखती है। निर्धारित समय पर सदस्यता, सक्रिय सदस्यता तथा मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के संगठनात्मक चुनाव कराना हमारी विशेषता है। उसी अनुसार देशभर में प्राथमिक सदस्यता अभियान का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा संगठनात्मक चुनाव की प्राथमिक तैयारियां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में रखी गयी थी। इस वर्ष माह नवम्बर तक सभी स्तर पर संगठनात्मक चुनाव सम्पन्न कराने का निर्णय हुआ है। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि हमारी सभी राज्य इकाईयां इन चुनावों को सम्पन्न करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही रहेगा कि हम सभी लोग कार्यकर्ता भाव से समन्वय बनाते हुए संगठन का निर्वाचन सम्पन्न करेंगे। दलीय परंपरा, मान्यता और दलीय साख का हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। ।

संगठनात्मक चुनावों में हमें यथासंभव आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है साथ ही आन्तरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति हमारा आग्रह होना चाहिए।

कोई भी राजनैतिक निर्णय लेने से पूर्व यथासंभव सभी संबंधित कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। निर्णय के सभी पहलुओं पर खुली बहस होनी चाहिए परन्तु एक बार निर्णय हो जाने के बाद उस पर किसी प्रकार की बहस और टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बल्कि हम सभी लोगों को उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में लग जाना चाहिए।

fodkI dh vun[kh

एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास की जो तीव्र प्रक्रियाएं प्रारम्भ हुई थी उसकी गति निरंतर मन्द पड़ती जा रही है और विकास की अनेक योजनाएं ठण्डे बस्ते में डाल दी गई हैं। भाजपा एवं गठबन्धन शासित राज्यों में केन्द्र के वांछित सहयोग के बिना भी विकास के अनेक सराहनीय कार्य चल रहे हैं। इस हेतु वे सभी सरकारें बधाई की पात्र हैं।

विकास को अवरुद्ध करने वाले कई प्रयासों के बावजूद पिछले दिनों सरदार सरोवर बांध परियोजना पर गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों ने जनहित में जो दृढ़ता दिखाई है वे उसके लिए बधाई की पात्र हैं।

vkg~oku

अध्यक्ष बनने के बाद मैंने देश के अनेक राज्यों को दौरा किया। दौरे में राज्यों के नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श हुआ। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हमारे कार्यकर्ता हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है। बंधुओं, अगला वर्ष भाजपा के लिए कसौटी का वर्ष है। 2007 के पूर्वार्द्ध में जहां पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा एवं मणिपुर तथा उत्तरार्द्ध में गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। हम सबको इसके लिए अभी से कमर

कसनी होगी। कांग्रेस और वामपंथी दलों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है और उनसे जनता की कोई आशा शेष नहीं है। अतः स्वाभाविक रूप से जनमानस के लिए हम आशा की किरण हैं।

हताशा और निराशा के इस वातावरण से देश को निकालकर पुनः समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर ले जाने का दायित्व नियति ने हम पर सौंपा है। हमें अपनी कर्मठता, जीवटता और सुचिता से इस दायित्व का नैतिकता से निर्वहन करना ही होगा। यदि हम इस दायित्व के निर्वहन में तनिक भी चूक गए तो भारत का भावी इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाला कल हमारा है और वैभवशाली भारत के निर्माण में हमारी भूमिका सुनिश्चित है।

यह संघर्ष की ऐसी बेला है जिसमें एक भी पल गंवाए बिना हमें अपनी–अपनी भूमिका के लिए उठ खड़े होना है। हमारी विजय सुनिश्चित है।

/kU ;okn]

&&&&&&